www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 05 || लखनऊ
रविवार
05 अप्रैल 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:53
सूर्यास्तः 06:25
अधिकतमः 32°00
न्यूनतमः 19°00

पेज 03

विशेष समाचार

बंगाल में पार्टियां बदलीं, सरकार ... >> पेज 02

पंचायत चुनाव में देरी पर सपा छात्र ... >>पेज 04

'सैयारा' के बाद अहान पांडे को मिली ...

शिक्षामित्रों को इसी महीने से मिलेंगे 18 हजार

अनुदेशकों को भी बढ़ा मानदेय मिलेगा, सीएम योगी का ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। सीएम योगी ने वाराणसी में शनिवार को 1.42 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। कहा- इसी महीने से शिक्षामित्रों को 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। अभी तक शिक्षामित्रों को 10 हजार और अनुदेशकों को 9 हजार रुपए ही मिल रहे थे। सीएम ने 26 फरवरी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। यूपी में 2001 से शिक्षामित्रों की नियुक्ति शुरू हुई थी। सपा की सरकार ने 2013-14 में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। जिनका समायोजन नहीं हुआ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 12 सितंबर, 2015 को इन शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया। सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 25 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। शिक्षामित्रों को आयु सीमा के साथ 25 बोनस अंक भी दिए गए। उसके बाद 2019 में फिर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा की। इसमें भी शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट के साथ बोनस अंक दिए गए। दोनों भर्ती में करीब 13 हजार से अधिक शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बने। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के तत्कालीन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने केवल एक वर्ष के लिए 17,000 रुपए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

>> (शेष पेज 04 पर)

- सीएम ने शिवपुर के परिषदीय स्कूल के बच्चों को खुद कंधे पर स्कूल बैग पहनाया। गिफ्ट और किताबें दीं।
- सीएम योगी ने बच्चों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी देखी और उनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा।

> सीएम ने सपा सरकार पर हमला किया। कहा- 2017 से पहले सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं थी। उनके लोग नकल कराते थे, ताकि उनके स्कूलों में पढ़ाई न हो। इस तरह की कामचलाऊ व्यवस्था से समाज आगे नहीं बढ़ता। इससे पहले सीएम ने काल भैरव के दर्शन किए। चौखट को हाथ से छूकर प्रणाम किया। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं और पुजारियों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

सहायक अध्यापक से फिर शिक्षामित्र बना दिए गए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक साथ 1.72 लाख सहायक अध्यापक फिर शिक्षामित्र बना दिए गए। 50 हजार रुपए वेतन पाने वाले फिर 3500 रुपए महीने के मानदेय पर आ गए।इसके खिलाफ प्रदेश भर से आए शिक्षामित्रों ने लखनऊ में गोमती के तट पर बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए महीने करने की घोषणा की। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती में वरीयता देने के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा भी की।

भाजपा सरकार ने 2017 में समाधान का किया था वादा

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। शिक्षामित्रों की संख्या के कारण ही परिषदीय स्कूलों में यह अनुपात 1:22 है। शिक्षा मित्रों की संख्याबल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल सहायक टीचर भर्ती की आवश्यकता नहीं है। अनुदेशकों का मानदेय वर्ष 2017 में करीब 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया।

शिक्षा मित्रों का सफर रहा उतार-चढ़ाव भरा

- शिक्षामित्रों का नियमितीकरण करें 2001 में नियुक्ति के समय मात्र 1500 रुपए मानदेय मिलता था। एक साल में बढ़ाकर 2250 किया गया।
- 2005 में मुलायम सिंह सरकार ने 150 रुपए बढ़ाकर 2400 किया। मायावती सरकार में 600 रुपए बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। उसी दौरान शिक्षा मित्रों के लिए दो वर्षीय बीटीसी कोर्स शुरू हुआ।
- 2014 में कोर्स पूरा होने पर अखिलेश सरकार ने जुलाई में उन्हें पूर्णकालिक अध्यापक बना दिया, तब 43 हजार रुपए मिलते थे।
- लेकिन 25 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समायोजन रद्द हो गया।
- 2017 से फिर शिक्षा मित्र पद पर वापस, मानदेय 3500 रुपए था। ट्विटर योगी सरकार ने उसी साल 10 हजार रुपये कर दिया, जो अब तक चल रहा था।

केरलम में 339 करोड़पति कैंडिडेट, 38% पर क्रिमिनल केस

5 साल में 48% बढ़े करोड़पति उम्मीदवार, 54% प्रत्याशी ग्रेजुएट नहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

तिरुवनंतपुरम। केरलम विधानसभा चुनाव में 38% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। BJP के 59 और CPI(M) के 51 उम्मीदवार हैं। वहीं, 23% पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने विधानसभा चुनाव लड़ रहे कुल 883 में से 863 उम्मीदवारों के एफिडेविट का एनालिसिस कर शनिवार को यह रिपोर्ट जारी की। 339 करोड़पति प्रत्याशी हैं। यानी हर 5 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 2021 में राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में 27% उम्मीदवार ही करोड़पति थे लेकिन 2026 में ये नंबर बढ़कर 39% हो गया। यानी 5 साल में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 48% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 54% उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं हैं। वहीं, 48% उम्मीदवारों की शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच है। राज्य में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को मतदान होगा। रिजल्ट 4 मई को आएगा। कांग्रेस भाजपा और CPI के 255 में से 182 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस चल रहे हैं। 17 उम्मीदवारों पर हत्या से जुड़े आरोप हैं। वहीं, 15 पर महिला अपराध से जुड़े केस हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

संसद गाली देने-माइक तोड़ने नहीं गया : राघव

मेरे खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक, स्क्रिप्टेड कैंपेन

तमसा संकेत, एजेंसी

लुधियाना। आम आदमी पार्टी (AAP) के आरोपों को लेकर सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को दूसरा वीडियो जारी किया। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया (X) पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया झूठ भी सच लगने लगता। 3 आरोपों में जीरो सच्चाई है। राघव ने वीडियो में कहा- कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। वही भाषा, वही बातें, वही आरोप। यह कोई को-इंसिडेंस नहीं, बल्कि एक को-ऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए। फिर लगा कि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो कहीं लोग मान न लें।

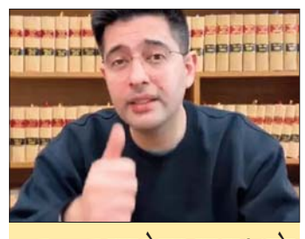

> राघव ने कहा- मुझ पर 3 आरोप लगाए, जिसकी वजह से मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं संसद में शोर मचाने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया, बल्कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए गया हूं। माइक तोड़ने की बात का सीधा संबंध आप के दूसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जोड़ा जा रहा है।

फास्ट न्यूज

भारत-चीन सीमा पर बढ़ेगा टूरिज्म

सुनील थपलियाल।
उत्तरकाशी। उत्तराखंड की फेमस नेलांग घाटी का अब पर्यटक पूरे साल लुत्फ उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सीमांत इलाके में जहां पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, बदलते मौसम और लद्दाख जैसा अनुभव लेने का मौका मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू

शिमला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर शाम ताजा हिमपात हुआ। अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ गई। इससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। अटल टनल के अलावा दारचा, गोंदला, रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा और स्पीति वैली में भी बर्फबारी हो रही है। दोपहर बाद शिमला जिला के ठियोग व आसपास के क्षेत्रों और हमीरपुर के सुजानपुर भी भारी ओलावृष्टि हुई। इससे सेब की फ्लावरिंग, मटर और फूलगोभी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान सराहन में 32.7 मिली, धर्मशाला 32.2, जोत 22.4, घाघस 19.4, मुरारी देवी 17.4 और मनाली में 17.0 मिमी बारिश हुई।

जज पर एडिशनल सेशन जज के घर चोरी के आरोप

लुधियाना। पंजाब के पटियाला में सिविल जज पर एडिशनल सेशन जज के घर में चोरी करने के आरोप लगे हैं। सिविल जज के खिलाफ घटना के सात महीने बाद 21 मार्च को FIR दर्ज की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिविल जज द्वारा लगाई गई बेल भी कोर्ट ने रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि एक मृतक सहकर्मी के आवास से संदिग्ध परिस्थितियों में भारी मात्रा में सोना और अभूषण निकालना गंभीर आरोप है।

केदारनाथ में हुई भारी बर्फबारी, अटल टनल बंद

यूपी में बिजली गिरने से 5 मौतें, एमपी-राजस्थान में ओले गिर सकते हैं

अलर्ट

तमसा संकेत, एजेंसी

भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया है। रोहतांग दर्रे के पास भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई है। इधर, लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। राजस्थान में शुक्रवार को रेगिस्तानी जिले जैसलमेर-बीकानेर में जमकर ओले गिरे। अजमेर-ब्यावर में आंधी से पेड़ गिर गए और टीनशेड उड़ गए। अगले तीन दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की कोसीकला अनाज मंडी में 10 हजार बोरियों में रखा 5 हजार क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। इससे पहले राज्य में अलग-अलग जगह बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, पंजाब सहित 11 राज्यों में शनिवार को तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 36 जिलों में बारिश हुई, आज ओले गिरने की आशंका है।

ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला

एक की मौत, इजराइल ने पेट्रोकेमिकल जोन पर एयरस्ट्राइक की, 3 कंपनियां तबाह

वॉरअलर्ट

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान के बुशहर में शनिवार को न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे एक सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। वहीं इजराइल ने ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में महशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया। इजराइल के सुरक्षा सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि ये हमले उसकी वायुसेना ने किए हैं। इस हमले में तीन कंपनियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, हमलों में पांच लोग घायल हुए हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में एक रेड क्रिसेंट कर्मी की मौत हो गई। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इस्फहान प्रांत के मोबारेकेह इलाके में हुआ। हालांकि, इस हमले पर अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रेड क्रिसेंट एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन है, जो आपदा और युद्ध के समय राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।

ईरान में अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर 55 लाख का इनाम

ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन ईरानी तोमान (लगभग 55 लाख रुपए) के इनाम का ऐलान किया है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के एक एंकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर सरकारी अधिकारी या सेना को सौंपे।

> ईरान ने कहा कि वह मौजूदा युद्ध खत्म करने के लिए समझौते के बजाय ठोस और स्थायी समाधान चाहता है।

रमत गन और तेल अवीव में ईरानी हमलों से नुकसान

शनिवार को ईरान की ओर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उनके मलबे गिरने से इजरायल के मध्य हिस्से रमत गन में एक रिहायशी इलाके को नुकसान पहुंचा। मौके पर पहुंचे इमरजेंसी और रेस्क्यू टीमें राहत कार्य में जुट गईं। वहीं इसी हमले के कारण तेल अवीव के एक स्कूल भवन को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। ईरान के साथ जारी संघर्ष के चलते 28 फरवरी से पूरे इज़राइल में स्कूल बंद हैं।

ईरान ने अमेरिका के दो लड़ाकू विमान गिराए

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के दो लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है। वहीं, ट्रम्प ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रम्प ने कहा, हम युद्ध में हैं। उन्होंने यह बात अमेरिकी मीडिया NBC से एक फोन इंटरव्यू में कही।

जनसभा उन्हें नाराज करने वाले बयान दे रही, इससे वहां भारतीयों पर मुसीबत आ सकती है

कांग्रेस चाहती है खाड़ी देश भारत को दुश्मन समझें : मोदी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम/चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरलम के थिरुवल्ला में जनसभा की। उन्होंने कहा- कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशियाई देश भारत को अपना दुश्मन समझें। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दें, कोई ऐसा बयान दे दें जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को वहां से बाहर निकलने में मुसीबत आ जाए, इसलिए कांग्रेस खाड़ी देशों को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और कांग्रेस को मोदी को गालियां देने का मौका मिले। मैं कांग्रेस, UDF, LDF के लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन केरलम के लाखों भाई-बहन वहां हैं उनकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। चुनाव आयोग ने भबानीपुर में सुवेंदु अधिकारी के नामांकन में लापरवाही को लेकर कोलकाता पुलिस के 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। रोड शो के दौरान BJP और TMC समर्थक आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव और ट्रैफिक जाम हो गया था। बहरामपुर में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धक्का-मुक्की की।

>> (शेष पेज 04 पर)

मोदी बोले- केरलम को बहुत फायदा, मेरा नुकसान

पीएम मोदी ने कहा- इस चुनाव में केरलम को कुछ फायदा होने की संभावना है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब मोदी को नुकसान हो रहा है तो केरलम को कैसे फायदा हो सकता है? मतल अनूप, जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले पांच सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश में घूमकर जानकारी और जानकारी इकट्ठा की है। एक तरह से, वह मेरे पक्के साथी रहे हैं और काम के लिए मेरे दाहिने हाथ की तरह बन गए हैं।

> मोदी ने कहा- इस बार के चुनाव में केरलम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सरकार जाएगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की सरकार आएगी। मैं पहले भी केरलम आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। केरल एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा।

पीएम बोले- राज्य में डबल इंजन की सरकार से सभी रुकावटें दूर होगीं

पीएम ने कहा कि यहां सबरीमाला रेलवे प्रोजेक्ट इस इलाके में नई संभावनाएं खोल सकता है। यह सबरीमाला से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, लोकल बिजनेस को नई रफ्तार देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। जब BJP की डबल इंजन वाली सरकार सत्ता में आएगी, तो ऐसी सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम बोले 33 फीसदी महिलाएं चुन कर आएंगी।

महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में कार गिरी, 9 मौतें

सभी एक ही परिवार के, इनमें 6 बच्चे भी शामिल

हादसा

तमसा संकेत, एजेंसी

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार के कुएं में गिरने से एक परिवार के छह बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे डिंडोरी शहर के शिवाजी नगर इलाके में हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार एक बैंक्वेट हॉल में फंक्शन में शामिल होने के बाद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार वेन्यू के पास एक कुएं में गिर गई। पुलिस के अनुसार, मरने वालों की पहचान सुनील दत्तू दरगुडे (32), उनकी पत्नी रेशमा, एक अन्य महिला आशा अनिल दरगुडे (32) और परिवार के छह बच्चों (पांच लड़कियां और एक लड़का) के रूप में हुई है।

- क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उस वक्त उसमें शव मौजूद थे।
- कुंए से निकाले जाने के बाद कार को बाहर खड़ा किया गया। कार का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट गया था।

सम्पादकीय

भाजपा ने दिखाया आरक्षण विरोधी चेहरा

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों खराब है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनके बेटे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अस्पताल में अपनी मां के साथ बने हुए हैं। उन्होंने बुधवार को केरलम का चुनावी दौरा भी रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी मां की तबियत की फिक्र थी। ऐसे मौके पर भी भाजपा राजनीतिक वार करने से बाज़ नहीं आई। जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हुईं, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड पर बने कार्यालय को खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। इसके अलावा यूथ कांग्रेस को भी दफ्तर खाली करने का नोटिस भेजा गया। हालांकि कांग्रेस का नया दफ्तर इंदिरा भवन से चल रहा है, लेकिन 24 अकबर रोड का ऐतिहासिक महत्व है, जिसे भाजपा खत्म करना चाहती है। इधर भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के इलाज में भी राजनीति का मौका तलाश लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछ लिया कि वह अपनी मां का ऐसे अस्पताल में क्यों इलाज करा रहे हैं जहां आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है।राजनीतिक विश्लेषण निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60 प्रतिशत आरक्षण के डॉक्टर मिलते, क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरुप बासु कर रहे हैं जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं हैं। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है? जार्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं?' निशिकांत दुबे इससे पहले भी जिस तरह से नेहरूजी और इंदिरा गांधी के बारे में बेसिरपैर की बातें करते रहे हैं, उसमें उनसे किसी सदाशयता या शिष्टता की उम्मीद नहीं है। इस बार सोनिया गांधी के नाम पर उन्होंने राहुल गांधी को घेरने का मौका ढूंढ लिया, लेकिन इसमें दो बड़ी गलतियां सांसद दुबे कर बैठे। एक तो उन्होंने उस एम्स की श्रेष्ठता पर सवाल उठाए, जो भारत में करोड़ों लोगों के लिए इलाज की बड़ी आस है। एम्स के नाम पर नरेन्द्र मोदी ने खूब राजनैतिक रोटियां सेंकी है। कांग्रेस शासनकाल में केवल 7 एम्स थे, हमने देश भर में 20 एम्स बनवाए, ऐसी बातें बोलकर भाजपा अपनी काबिलियत दिखाती है। लेकिन निशिकांत दुबे तो बता रहे हैं कि एम्स में सही इलाज नहीं होता, इसलिए राहुल गांधी ने सर गंगाराम को अपनी मां के इलाज के लिए चुना। निशिकांत दुबे ने सत्ता में बैठकर जिस तरह अपनी ही सरकार द्वारा संचालित एम्स में अच्छे इलाज के लिए संदेह जाहिर किया है, वह राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि उनकी पार्टी भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो पिछले साल जनवरी में उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा और दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर एम्स पर करोड़ों लोगों की निर्भरता और उस की बदहाली की तरफ ध्यान दिलाया था। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि, 'हाल ही में मैंने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में ये लोग मेट्रो स्टेशन के सब-वे के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां पीने के पानी या शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली एम्स में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का आना यह भी दर्शाता है कि लोगों को जहां वे रहते हैं, वहां सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे।' राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा, 'इनमें से कई मरीज देश के दूर-दराज इलाकों से आते हैं, अपनी जीवन भर की बचत खर्च करते हैं, और भारत के इस प्रमुख अस्पताल में इलाज के लिए महीनों तक प्रतीक्षा करते हैं। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी को भी ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वह पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। दिल्ली एम्स उत्कृष्ट और किफायती इलाज प्रदान करता है, लेकिन मरीजों और उनके परिवारों की स्थिति से पता चलता है कि अब भी करोड़ों भारतीयों के पास बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है।' इस पत्र से राहुल गांधी के सरोकार स्पष्ट हो जाते हैं कि वे दिल्ली एम्स को उत्कृष्ट मानते हैं और उनकी चिंता के दायरे में करोड़ों परिवार आते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे की चिंता यह है कि सोनिया गांधी का इलाज सर गंगाराम में क्यों हो रहा है। और जिस तरह आरक्षण का मुद्दा यहां उन्होंने उठाया, उसमें भी भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा फिर उजागर हो गया। एक तरफ यूजीसी के नए नियमों के बहाने दलितों और पिछड़ों की हितरक्षा का दिखावा और दूसरी तरफ आरक्षण के हक को कम काबिलियत के समान बताने की खोटी नीयत, यही खेल भाजपा इस समय खेल रही है। जबकि राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग ही इसलिए करते हैं ताकि दलित और पिछड़ी आबादी को उसका पूरा हक मिले। आरक्षण की सीमा बढ़े ताकि शिक्षा, नौकरी या जीवन के अन्य क्षेत्रों में दलितों की भागीदारी बढ़े, क्योंकि इसी के बाद समाज में समानता स्थापित हो सकेगी।

बंगाल में पार्टियां बदलीं, सरकार बदली, सियासी चेहरे बदले, पुलिस तंत्र भी बदलता गया

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भले ही बंगाल में 6 मई को मतदान पूरा हो जाएगा, लेकिन चुनाव बाद की हिंसा का चुनाव से सीधा संबंध होता है, जो चुनाव आयोग को इसमें एक हितधारक बनाता है। नई सरकार बनने के बाद भी, बलों को वापस बुलाने के लिए राज्य को चुनाव आयोग या केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखना होगा।

पश्चिम बंगाल की बदहाल कानून व्यवस्था की गूंज राष्ट्रीय पटल पर हमेशा होती है। इस मुद्दे पर विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे बंगाल की छवि को खराब करने की साजिश बताती हैं। इस बार भी चुनाव में कानून-व्यवस्था ज्वलंत मुद्दा है। यहां ईडी और एनआईए पर भी हमले हो चुके हैं।बंगाल में पार्टियां बदलीं, सरकार बदली, सियासी चेहरे बदले, पुलिस तंत्र भी बदलता गया, नहीं बदली तो बस कानून एवं व्यवस्था की बदतर हालत। समय के साथ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के गठन हुए, कमिश्नरेट बने, दर्जनों थाने खुले, विभिन्न पुलिस प्रकोष्ठ के निर्माण हुए, ढेरों पद सृजित हुए, पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक हथियारों व उपकरणों से लैस किया गया, फिर भी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जस की तस है। वाममोर्चा के 34 वर्षों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के राज तक बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की बदहाली प्रत्येक चुनाव में बदस्तूर ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। भाजपा, कांग्रेस, वाममोर्चा से लेकर चुनावी मैदान में उतरे छोटे-बड़े सभी दल कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर तृणमूल पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी हर बार की तरह इसे विरोधी दलों की बंगाल की छवि बिगाड़ने की साजिश करार दे रही हैं। वहीं, तृणमूल के नेता-कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कोलकाता को देश का सबसे सुरक्षित शहर करार दिया है। आखिर बंगाल में कानून एवं व्यवस्था ध्वस्त क्यों है?इसके जवाब में कानून विशेषज्ञ बृजेश गिरि बताते हैं कि बंगाल में दशकों से एक ट्रेंड चलता आ रहा है, वह यह है कि जब जिस पार्टी के हाथों में सत्ता होगी, पुलिस पर पूरी तरह से उसी का नियंत्रण होगा। पुलिस सत्ताधारी पार्टी की कैडर बनकर रह गई है। वाममोर्चा के जमाने में तो थाने में घुसकर पुलिस वालों को धमकाया जाता था। थाने में तोड़फोड़ की कई

घटनाएं हो चुकी हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से काफी पहले केंद्रीय बल भेजा जाना और 294 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से लगभग आधी सीटें होने पर भी बंगाल में वहां की तरह 2 चरणों में मतदान कराया जाना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चुनाव आयोग इस राज्य को लेकर कितना सतर्क है। चुनाव की घोषणा से पहले बंगाल में तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता आई चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने राज्य के आला प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को हिंसा-मुक्त चुनाव कराने का बेहद कड़ा निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो यहां तक कहकर गए हैं कि पुलिस-प्रशासन ने अगर ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया तो आयोग को काम करवाना आता है। गौरतलब है कि बंगाल कानून को शर्मसार करने वाली घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है । बंगाल में कानून-व्यवस्था की इससे लज्जाजनक तस्वीर और क्या होगी कि 2014 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निवास स्थल से कुछ दूरी पर स्थित अलीपुर थाने में तृणमूल नेता के हमले के दौरान वहां ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए मेज के नीचे छिप गए थे। विरोधी दल लगातार कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते आए हैं।पिछले कई राज्यपाल भी इसे लेकर सवाल करते आए हैं। बोगटूई में लोगों के घरों में ताला जड़कर आग लगाकर जिंदा जलाकर मार डाला गया।कृष्णागंज में तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास और झालदा में कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की सरेआम गोली मारकर हत्याकर दी गई थी।माकपा के युवा संगठन डीवाईएफआई के कार्यकर्ता अनीस खान के घर में पुलिस की वर्दी में घुसकर उन्हें छत से फेंककर हत्या कर दी गई।संदेशखाली में पुलिस की नाक के नीचे बड़ी संख्या में महिलाओं का यौन उत्पीड़न व ईडी की टीम पर हमला।पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में विस्फोट कांड की तफ्तीश के सिलसिले में गई एनआईए की टीम पर हमला।2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा व पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में भारी रक्तपात इसकी वीभत्सता को और बढ़ाते हैं। राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस तो पिछले साल पंचायत चुनाव के समय सड़क पर उतर गए थे। लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने को उन्होंने इस चुनाव में भी मतदान के दिनों में लोगों के बीच रहने की बात कही है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में भ्रष्टाचार की तरह कानून-व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। राज्य में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग उठ चुकी है। जब तक पुलिस से सत्ताधारी पार्टी का नियंत्रण नहीं हटेगा, तब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार की उम्मीद करना बेमानी है। सत्ताधारी पार्टी और पुलिस के बीच स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देनी होगी। इस बार भी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शांतिपूर्वक बंगाल चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की है। चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मतगणना पूरी होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगी। चुनाव के बाद भी सीएपीएफ की कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी। यह तैनाती ईसीआई के अगले आदेश तक जारी रहेगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा त्रिपुरा के आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके तहत असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल तथा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हो रहा है । जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जिसे लोक सभा या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव या किसी संसदीय/विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है।

■ अशोक भाटिया

जन सुराज का...

कमलेश पांडेय

आखिर पश्चिम बंगाल में 'चुनावी जंगलराज' के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं?

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना वहां के कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है। चूंकि राज्य में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और राज्य प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है, इसलिए मौजूदा स्थिति के लिए ममता सरकार को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। बेहतर होगा पश्चिम बंगाल में 'चुनावी जंगलराज' के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो कि तमाम राजनीतिक अराजकता की जड़ बन चुके हैं! सवाल विधि के शासन का है जो विरोधाभासों से भरे पड़े संविधान के समक्ष दम तोड़ता प्रतीत हो रहा है, इसलिए संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई में भविष्य के लिए स्पष्ट नजीर दिखनी चाहिए अन्यथा भारत और भारतवासियों का भला नहीं होगा! दरअसल, मालदा के कयाचक क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने 1 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:30 बजे से 9 घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय में अधिकारियों को बंधक बनाया जहां उन्हें भोजन-पानी के बिना रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, मालदा डीएम व एसपी को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई बुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ₹नागरिक व पुलिस प्रशासन की पूर्ण विफलता₹ बताया तथा सीबीआई या एनआईए से जांच के निर्देश दिए जिसे चुनाव आयोग ने सीबीआई को सौंप दिया। यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखी जा रही है जिसके राजनीतिक मायने खतरनाक हैं क्योंकि बीजेपी ने टीएमसी पर भीड़ भड़काने का आरोप लगाया, साथ ही इसे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता और नकली वोटरों के नाम

डिलीट होने का डर बताया। वहीं, टीएमसी ने बीजेपी व चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और एसआईआर को गंदी साजिश कहा। उल्लेखनीय है कि आगामी विधानसभा चुनावों (23-29 अप्रैल) से ठीक पहले इस विवाद के उभरने से राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हुए हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और इसे न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की सुनियोजित साजिश और अदालत के अधिकार को खुली चुनौती बताया। कोर्ट ने राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर सख्ती दिखाते हुए इसे कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, यह कोई सामान्य विरोध नहीं बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करने का पूर्वनियोजित प्रयास था। इससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठते हैं। आखिर रात 11 बजे तक डीएम-एसपी क्यों नहीं पहुंचे? जब राजनीतिक नेता मौके पर थे तो प्रशासन क्यों सो रहा था? इसे न्यायपालिका पर हमला बताते हुए घिनौना प्रयास कहा जो चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने का मकसद रखता था। ततपश्चात कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी, मालदा डीएम-एसपी को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को सुनवाई बुलाई। वहीं, चुनाव आयोग को एसआईआर से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने तथा भीड़ नियंत्रण (5 से अधिक लोगों पर रोक) के निर्देश दिए। साथ ही सीबीआई/एनआईए जांच का सुझाव भी दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा घटना पर चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए कहा कि राज्य प्रशासन उनके नियंत्रण में नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घटना की जानकारी आधी रात को एक पत्रकार से मिली और एसआईआर प्रक्रिया से लोगों का गुस्सा जायज है। ममता ने कहा, मुझे नहीं पता वे कौन थे जिन्होंने अधिकारियों का घेराव किया लेकिन एसआईआर से लोग नाराज हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले शीर्ष अधिकारियों के तबादले से सुपर राष्ट्रपति शासन,चल रहा है। बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए जांच की मांग की और कहा, मेरी सारी शक्तियां छीन ली गईं। ममता का यह बयान सागरदिघी या धूमुरपहाड़ी रैली में आया जहां उन्होंने टीएमसी को निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह चुनाव आयोग व बीजेपी पर हमला है, जो आगामी चुनावों में ध्रुवीकरण बढ़ा रहा है। बेहतर होगा कि इस मामले में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के अलावा मालदा डीएम, ,सपी को अविलंब नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि चुनावी दिनों में इन सबकी अविवेकी हरकतों से एक निर्वाचित सरकार की बदनामी बढ़ी है और इसके चुनावी दुष्प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे प्रशासनिक विफलता और आपराधिक अवमानना करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, शोध का विषय है। उचित तो यह होगा कि इस उपद्रव में शामिल लोगों के व्यवहार को अराजक घोषित करते हुए इनके मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड आदि जब्त किया जाए और तमाम सरकारी सुविधाओं से ऐसे उग्र लोगों को वंचित किया जाए। साथ ही इन्हें उकसाने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए और इसके प्रदेश अध्यक्ष को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।

पान जैसी नाजुक...

अमरपाल सिंह वर्मा

जलवायु परिवर्तनः पान की पारंपरिक खेती खतरे में

राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील के कुछ गांव आजकल किसी रिपोर्ट के आंकड़े नहीं बल्कि एक धीमी त्रासदी की तरह सामने आते हैं। कभी यहां पान की बेलें सिर्फ खेतों में नहीं, लोगों की जिंदगी में भी लहलहाती थीं। आज वही बेलें सिकुड़ गई हैं और उनके साथ सिकुड़ गई है एक पूरे समुदाय की आर्थिक और सामाजिक दुनिया। एक आज ये गांव खाली हो रहे हैं। वहां के ग्रामीण कामकाज के लिए बड़े शहरों में पलायन कर गए हैं। खाली पड़े मकान गांवों को भुतहा सा दर्शाते हैं। पिछले दिनों मैंने जब इस इलाके के बारे में सुना था तो एक बात बार-बार मन में आ रही थी कि क्या सचमुच यह सिर्फ मौसम की मार है? या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को 'जलवायु परिवर्तन' जैसे बड़े शब्दों के पीछे छिपा रहे हैं? यह सच है कि मौसम बदल गया है। सर्दियां पहले जैसी नहीं रही हैं, गर्मियां झुलसा देती हैं और बारिश अपने समय पर नहीं आती। पान जैसी नाजुक फसल के लिए यह बदलाव जानलेवा साबित हुआ है। मैं जब इस इलाके में गया तो गांवों की समृद्ध अर्थ व्यवस्था को उजड़े हुए पाया। खरैरी, बागरैन और खानखेड़ा गांवों के किसान बताते हैं कि पहले पान की एक बेल पंद्रह फीट तक जाती थी, अब सात-आठ फीट पर ही दम तोड़ देती है। पत्ते कम हो गए हैं, और जो हैं, वे भी अक्सर दागदार या जले हुए मिलते हैं। लेकिन यहां कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल कहानी वहां से शुरू होती है, जहां किसान मौसम से लड़ते-लड़ते थक जाता है और फिर उसे अहसास होता है कि इस लड़ाई में वह अकेला है। कोई उसके साथ नहीं है। पान की खेती आज भी फसल बीमा के दायरे से बाहर है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर हैरानी नहीं बल्कि चिंता होनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जब जोखिम बढ़ रहा है, तब सुरक्षा का दायरा क्यों

नहीं बढ़ता? क्या हमारी नीतियां केवल गेहूं-चावल जैसी मुख्यधारा की फसलों तक सीमित रह गई हैं? या फिर हम उन फसलों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो भले ही राष्ट्रीय आंकड़ों में बड़ी न दिखें लेकिन स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं? बयाना का खरैरी गांव इसका जीता-जागता उदाहरण है। कभी यहां पान की वजह से इतनी रौनक थी कि बैंक की मुख्य शाखा तक खुल गई थी। आज हालात ऐसे हैं कि यह बैंक भी अपना बोरिया-बिस्तर समेट चुका है। यह सिर्फ एक आर्थिक गिरावट नहीं, बल्कि एक पूरे दौर के खत्म होने की निशानी है। इसके बाद आता है पलायन। गांव के युवा अब खेतों में नहीं, शहरों की भीड़ में मिलते हैं। बड़े शहरों में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई हलवाई के यहां काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। यह बदलाव सिर्फ पेशे का नहीं है बल्कि पहचान का भी है। जो लोग कभी अपने खेतों के दम पर समृद्ध थे, वे अब शहरों में मजदूरों की कतार का हिस्सा बन गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या हम गांवों को धीरे-धीरे खाली होते देखने के आदी हो चुके हैं? सरकार की भूमिका पर बात करना यहां जरूरी है लेकिन इसे केवल आलोचना के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में सदियों पुरानी खेती खत्म होने के कगार पर है।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

सौरभ वार्ष्णेय

तेल के खेल में सत्ता का नया केंद्र बनेगा भारत ?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए एक बयान से तेल के खेल में भारत सत्ता का नया केंद्र बन सकता है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक बयान दिया है जिसमें साफ-साफ कहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम भारी मात्रा में तेल और गैस के उत्पादन और बिक्री में बहुत अच्छा तालमेल बिठा रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा भंडार है. अब हम कच्चे तेल के लिए मध्य पूर्व पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हैं और फिर भी हम वहां सहायता के लिए मौजूद हैं। हालांकि, ट्रंप ने भले ही वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा कर लिया हो लेकिन इसमें सबसे अधिक फायदा भारत को हो सकता है। भारत इसमें सत्ता का केंद्र बन सकता है ? यानी भारत तेल के खेल में विश्व ऊर्जा का केंद्र बन सकता है क्योंकि भारत भले ही दूसरे देशों से कच्चे तेलों का निर्यात करता हो लेकिन कच्चे तेल की रिफाइनिंग के लिए अन्य देशों को हम भारत पर ही निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि रिफाइनरी के मामले में भारत दुनिया के सभी देशों से आगे हैं। अगर अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल को यूरोपियन देश को बेचता है तो इसमें भी भारत का ही सबसे अधिक फायदा है क्योंकि, यूरोपियन देश भारत से सबसे अधिक रिफाइंड तेल खरीदते हैं। अमेरिका खुद भारत से सबसे अधिक रिफाइंड तेल का आयात करता है। ऐसे में आने वाला भविष्य भारत के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। वैश्विक राजनीति में तेल (ऊर्जा) हमेशा से शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 20वीं सदी में (ऑर्गनाइजेशन ऑफ दॅ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) देशों और पश्चिमी शक्तियों के बीच तेल की राजनीति ने विश्व व्यवस्था को आकार दिया। आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में, बदलते ऊर्जा समीकरणों के बीच यह सवाल फिर उठ रहा है—क्या भारत इस तेल के खेल में सत्ता का नया केंद्र बन सकता है? इस बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़ा बदलाव आया। यूरोप ने रूसी तेल पर निर्भरता घटाई, वहीं भारत ने सस्ते रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत किया। इससे भारत न केवल लागत में बचत कर सका बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी बार्गेनिंग पॉवर भी बढ़ाई। ऐसे में समय में भारत की रणनीतिक स्थिति की बात करे तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति—मध्य पूर्व, रूस और एशिया के बीच—इसे एक प्राकृतिक ऊर्जा हब बनने का अवसर देती है। भारत ने एक ओर रूस से तेल आयात बढ़ाया, तो दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ संबंधों को भी संतुलित रखा। भारत रिफाइनिंग और निर्यात की ताकत रखता है। भारत केवल तेल आयातक ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख रिफाइनिंग हब भी बन चुका है। भारतीय रिफाइनरियां कच्चे तेल को प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों को पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात कर रही हैं। इस प्रक्रिया में भारत एक ₹मध्यस्थ शक्ति₹ के रूप में उभर रहा है—जहां कच्चा तेल कहीं से आता है और तैयार उत्पाद कहीं और जाता है। भारत के पास अवसर जरूर है लेकिन यह पूर्ण सत्ता केंद्र बनने से ज्यादा संतुलनकारी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की असली ताकत उसकी कूटनीति, बाजार आकार और ऊर्जा विविधीकरण में है न कि केवल तेल में। तेल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन इसके नियम बदल रहे हैं। भारत इस बदलते खेल का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। यदि वह अपनी ऊर्जा नीति में संतुलन, आत्मनिर्भरता और हरित विकल्पों को साथ लेकर चलता है तो भविष्य में वह केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का निर्णायक केंद्र भी बन सकता है। ओपेक दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है (ऑर्गनाइजेशन ऑफ दॅ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज), जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की तेल नीतियों का समन्वय करना और वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करना है। इसके संस्थापक १९६० में और इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में हैं। इसके मुख्य कार्य तेल उत्पादन को नियंत्रित करना, सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखना, उपभोक्ता देशों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि है। समय-समय पर बैठकों में यह तय करता है कि सदस्य देश कितना तेल उत्पादन करेंगे। अगर कीमतें गिरती हैं ? उत्पादन घटाया जाता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं ? उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस तरह वैश्विक तेल कीमतों पर सीधा प्रभाव डालता है। यह गठबंधन वैश्विक तेल बाजार पर और भी ज्यादा प्रभावशाली बन गया है।

यह केवल एक संगठन नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली ताकत है। इसके निर्णय से पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर देशों की अर्थव्यवस्था तक प्रभावित होती है। अगर हम भारत से रिफाइंड तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों की बात करें तो इसमें अमेरिका भी भारत से तेल आयात करता है।नीदरलैंड साल 2024 में रिफाइंड पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है। संयुक्त अरब अमीरात भी भारत से रिफाइंड तेल का प्रमुख आयातक है। रिफाइंड तेल खरीदार के रूप में सिंगापुर भी टॉप लिस्ट में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देश भी रिफाइंड के मामले में भारत पर निर्भर है।

धोनी के सच्चाई बताने के बाद लिया रिटायरमेंट : युवराज

कप्तान विराट, कोच ने स्पष्ट नहीं किया था कि आगे टीम में लेंगे या नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी से पता चला था कि अब चयनकर्ता उनके नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ही युवराज ने 10 जून 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। स्पोर्ट्स तक से बातचीत में युवराज ने कहा कि 36-37 साल की उम्र में जब वे टीम से अंदर-बाहर हो रहे थे, तब न तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA), न ही कप्तान विराट कोहली और न ही कोच रवि शास्त्री ने उनसे सीधे बात की। युवराज सिंह ने साल 2000 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और जून 2019 में संन्यास लिया। उन्होंने भारत के लिए 304 वनडे, 58 टी-20 और 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 11,000 से ज्यादा रन बनाए। वे 2007 टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे।

2011 वनडे वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे

युवराज सिंह ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। उन्होंने 8 पारियों में 90.50 की औसत से कुल 362 रन बनाए थे, जिसमें चार अर्धशतक और एक शतक शामिल था। उन्होंने टूर्नामेंट में 15 विकेट भी झटके थे। युवराज टूर्नामेंट में चार बार प्लेयर ऑफ द मैच बने और अंत में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। टूर्नामेंट के बाद युवराज को कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद उनका इलाज चला।

युवी ने कहा, 'उस समय मुझे लगा कि मैं बीच में फंस गया हूं। मैंने देश के लिए इतना क्रिकेट खेला, तो कम से कम थोड़ी इज्जत और साफ बात तो बनती थी, लेकिन मुझे कुछ भी साफ नहीं बताया गया।'

फिटनेस के नाम पर रिटायरमेंट के लिए दबाव बनाया गया

युवराज ने यह भी आरोप लगाया कि मैनेजमेंट ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। उनसे कहा गया था कि वे अब फिटनेस टेस्ट (यो-यो टेस्ट) पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें खेल को अलविदा कह देना चाहिए। इस पर उन्होंने साफ जवाब दिया कि रिटायर होना उनका फैसला होगा, जबकि टीम में खिलाना या नहीं खिलाना मैनेजमेंट का निर्णय है।

धोनी ने फोन पर बताया था सच

युवराज ने कहा कि उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को फोन किया। धोनी उस समय कप्तान नहीं थे, लेकिन वे पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। युवराज के मुताबिक, 'धोनी ने मुझे सही नजरिया दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिलेक्टर्स अब आगे की तरफ देख रहे हैं।

युवराज ने यह भी बताया कि वे अब तक कमेंट्री से दूर क्यों रहे। उन्होंने साफ कहा कि वे उन लोगों के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहते, जिन्होंने उनके बारे में निजी (पर्सनल) टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा, 'अब जब मैं रिटायर हो चुका हूं, तो इस बारे में खुलकर बोल सकता हूं। असली वजह ये है कि कुछ लोगों ने मेरे खेल पर नहीं, बल्कि मुझ पर पर्सनल कमेंट किए थे। खेल की बात समझ में आती है, लेकिन पर्सनल बातें आप कभी नहीं भूलते।'

युवराज के नाम भारत के लिए टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक

2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पहला टी-20 वर्ल्ड कप जीता था। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने इसी मैच में महज 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। यह आज भी भारत की ओर से टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड है। आउट होने से पहले युवराज ने 16 गेंदों में 58 रन की विस्फोटक पारी खेली थी।

वर्ल्ड कप 2011 के बाद सिर्फ एक शतक लगा सके थे

युवी युवराज ने कैंसर का इलाज कराने के बाद 2012 में वापसी की, लेकिन उनके खेल में पहले जैसी चमक नहीं रही। युवी ने वर्ल्ड कप 2011 के बाद खेले 30 वनडे में 27.08 की औसत 650 रन बनाए। इसमें सिर्फ एक शतक था। इसी दौरान उन्होंने 35 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 25.41 की औसत से 610 रन बनाए। अपने इंटरनेशनल करियर में 148 विकेट लेने वाले युवी ने अप्रैल 2011 के बाद भारत के लिए सिर्फ 22 विकेट झटके।

स्लो ओवर के लिए अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना

अब एक और गलती की तो पंजाब के कप्तान पर लगेगा एक मैच का बैन

नई दिल्ली, एजेंसी

IPL के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, लेकिन इस मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह इस सीजन का पंजाब किंग्स का दूसरा ओवर-रेट अपराध है। इसलिए सिर्फ कप्तान ही नहीं, पूरी प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर को भी सजा मिली है। बाकी सभी खिलाड़ियों पर 6 लाख या उनके मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उतना जुर्माना लगाया गया है। IPL के नियमों के मुताबिक, अगर अब टीम से फिर ऐसी गलती होती है तो अय्यर पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और एक मैच का बैन भी झेलना पड़ेगा। पंजाब को अभी लीग स्टेज में 12 से ज्यादा मैच खेलने हैं, ऐसे में अब गलती की गुंजाइश बहुत कम बची है। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी से टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने 29 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेली। उनकी नेहल

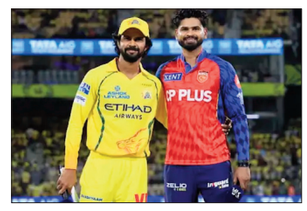

वाधेरा के साथ 59 रन की साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पंजाब किंग्स को जीत के लिए 209 रन का टारगेट मिला था, जिसे उन्होंने 5 विकेट खोकर आराम से हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 209 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। चेन्नई की ओर से युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने 43 गेंदों में 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (28 रन) के साथ 96 रनों की साझेदारी की। हालांकि, पंजाब की शुरुआत भी प्रियांश आर्य की 11 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी से हुई।

फास्ट न्यूज

परवीन बाबी को सिगरेट पीते देख डायरेक्टर ने फिल्म दी

मुंबई। करीब साढ़े 400 साल पहले पश्तून बाबी वंश मुगल शासक हुमायूं के साथ गुजरात पहुंचा। यह अफगानिस्तान का शाही परिवार था, जो मुगल साम्राज्य का अहम हिस्सा बना और कई रियासतों पर शासन किया। मुगल सत्ता कमजोर होने पर बाबी और मराठा (गायकवाड़ वंश) में जंग हुई, जिसमें मराठाओं ने अधिकांश गुजरात पर कब्जा किया, लेकिन बाबी ने जुनागढ़, राधनपुर और बालासिनोर पर शासन जारी रखा।

कार्टियर घड़ियों से 300% तक लाभ, रोलेक्स पिछड़ी

म्यूनिख/पेरिस। क्या आपकी कलाई पर बंधी घड़ी आपके बैंक एफडी, शेयर या रियल एस्टेट से बेहतर रिटर्न दे सकती है? लग्जरी वॉच मार्केट के ताजा आंकड़े कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ऑनलाइन वॉच मार्केटप्लेस 'क्रोनो24' की रिपोर्ट से एक दिलचस्प ट्रेंड निकलकर सामने आया है। वो ट्रेंड यह है कि महंगे और हाई-एंड वॉच मॉडल रोलेक्स, पाटेक फिलिप की तुलना में कार्टियर जैसी मिड रेंज के लग्जरी ब्रांड्स ने बेहतर मुनाफा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से लेकर 2026 के दौरान पेरिस स्थित ज्वेलर कंपनी कार्टियर की 'टैंक वर्मील' घड़ी की कीमत में करीब 300% की वृद्धि देखी गई। दिलचस्प है कि सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली टॉप-20 घड़ियों की लिस्ट में रोलेक्स का कोई भी मॉडल जगह नहीं बना पाया। रोलेक्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली डेटजस्ट 41 की वैल्यू साल 2018 से अब तक केवल 59 फीसदी ही बढ़ी है।

पाकिस्तान में डीजल 55% और पेट्रोल 43% महंगा

नई दिल्ली। पाकिस्तान में डीजल-पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। एक लीटर पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपया (पाकिस्तानी रुपया) के पार पहुंच गया है। सरकार ने पेट्रोल में 43% और हाई-स्पीड डीजल (HSD) के दाम में 55% का इजाफा किया है। यह फैसला अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद लिया गया है। नई दरें गुरुवार आधी रात से लागू हो गई हैं।

सुनंदा शर्मा को टच करने कूदा फैन

डरकर चिल्लाई सिंगर, स्टेज छोड़ा, बाउंसरों ने युवक को स्टेज से नीचे फेंका

जालंधर, एजेंसी

पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने गाजियाबाद में बीच में ही लाइव शो कैंसिल कर दिया और परफॉर्मेंस छोड़कर चली गईं। 3 अप्रैल की रात आरकेजीआईटी कॉलेज में चल रहे शो के दौरान अचानक एक युवक स्टेज पर चढ़ गया और उन्हें छूने की कोशिश करने लगा और उनके पैरों में गिर पड़ा। अचानक हुई इस घटना से सुनंदा घबरा गईं। जैसे ही युवक ने उन्हें छुआ, वह जोर से चीखीं और भागकर स्टेज के पीछे चली गईं। माइक ऑन होने की वजह से उनकी चीख साफ सुनाई दी, जिससे माहौल अफरा-तफरी में बदल गया। युवक करीब 2 मिनट तक स्टेज पर रहा और शाहरुख खान के सिग्नेजर स्टाइल में वाहें फैलाकर स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा। आवाज सुनते ही पुलिस तुरंत स्टेज पर पहुंची और युवक को वहां से हटाया।

बाउंसरों ने भी उसे पकड़कर स्टेज से नीचे उतारा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक उसी कॉलेज का छात्र है। इस घटना के बाद सुनंदा इतनी डर गईं कि दोबारा स्टेज पर नहीं लौटीं। नीचे मौजूद लोग उन्हें वापस बुलाते रहे, लेकिन उनकी टीम ने शो को बीच में ही कैंसिल करने का फैसला लिया। शो रद्द होने की घोषणा के बाद छात्र निराश होकर वापस लौट गए।

डायरेक्टर ने शूटिंग से एक्टर का लुक शेयर किया, शरवरी के साथ करेंगे रोमांस

'सैयारा' के बाद अहान पांडे को मिली दूसरी फिल्म

अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में 500 रुपए करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

मुंबई, एजेंसी

फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म अभी अनटाइटल्ड है और यह यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनेगी। जिसमें सैयारा से डेब्यू करने वाले अहान पांडे लीड रोल में होंगे। इसके अलावा फिल्म में शरवरी वाघ, ऐश्वर्य ठाकरे और बॉबी देओल भी होंगे। फिल्म को लेकर जानकारी देते हुए अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "और यह शुरू होता है।" साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें अहान पांडे की इंटेंस आंखें और एक क्लैपबोर्ड दिखाई दे रहा है।

फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन भी होगा

फिल्म को लेकर आईएएनएस के साथ बातचीत में एक सूत्र ने बताया कि सैयारा की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद अहान पांडे को जेन Z के प्रमुख मेल एक्टर्स में माना जा रहा है। वहीं शरवरी मुंज्या जैसी 100 करोड़ रुपए की फिल्म का हिस्सा रह चुकी हैं। अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में 500 रुपए करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

"सूत्र ने यह भी कहा कि अली अब्बास जफर इस जोड़ी के साथ एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें रोमांस मुख्य होगा और साथ में एक्शन भी शामिल रहेगा। लंबे समय बाद नए कलाकारों के साथ ऐसी फिल्म बनाई जा रही है, जिनकी बॉक्स ऑफिस पर पहचान बन चुकी है। सूत्र के अनुसार, दोनों कलाकारों ने अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने की क्षमता दिखाई है। इसी वजह से बड़े फिल्ममेकर इन पर भरोसा जता रहे हैं।"

23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट

ट्रम्प का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा गलत, अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान, एजेंसी

ईरान जंग के एक महीने बाद ट्रम्प ने 2 अप्रैल को अमेरिकी जनता को संबोधित किया। 19 मिनट के भाषण में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सेना को तबाह कर दिया है और उनके पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है।ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर कब्जा हो चुका है।

उनके विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ऐसे ही दावे किए। लेकिन हालात अब अलग कहानी बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के दो सैन्य विमान और सर्च ऑपरेशन में लगे दो ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर ईरान के हमले का शिकार हुए। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, 23 साल में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में गिराए गए। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के दौरान ऐसा

हुआ था। ईरानी मीडिया के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया गया। यह ईरान के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में उड़ान भर रहा था

F-15E फाइटर जेट के क्रू को ढूंढने के लिए अमेरिकी विमान A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ। A-10 हमले के बाद कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां पायलट ने सुरक्षित तरीके से इजेक्ट किया। पायलट सुरक्षित है, हालांकि विमान कुवैत में क्रैश हो गया। CBS के अनुसार, F-15E में दो क्रू मेंबर थे।

इनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दूसरा लापता है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि पैराशूट के जरिए बाहर निकला यह क्रू सदस्य देश के दक्षिणी हिस्से में उतरने का अनुमान है। वहीं, F-15E फाइटर जेट के रेस्क्यू के लिए 2 ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। उन पर भी हमला हुआ। हालांकि, इन पर मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि जंग शुरू होने के 35 दिन बाद भी अमेरिका अभी भी ईरान की रणनीति को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी विमानों और हेलिकॉप्टर पर हमले के पीछे मजीद एयर डिफेंस सिस्टम या कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल (शोल्डर-फायर मिसाइल) हो सकती हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसलिए वे इन मिसाइलों की रेंज में आ गए।

ईरान की रणनीति नहीं समझ पा रहा अमेरिका

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को ईरान के आसमान में बढ़त जरूर है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि कमजोर एयर डिफेंस होने के बावजूद ईरान ने इतने एडवांस अमेरिकी विमानों को कैसे निशाना बनाया? इसका जवाब है ईरान की 'असिमेट्रिक वॉरफेयर' यानी अलग तरीके से युद्ध लड़ने की रणनीति। ईरान जानता है कि सीधे युद्ध में अमेरिका से मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए कम संसाधनों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपना रहा है। वह अक्सर अमेरिका पर चौंकाने वाले हमले कर रहा है।

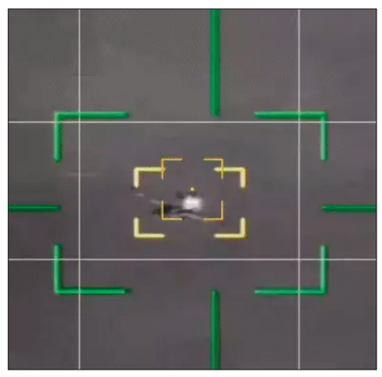

जीमेल यूजर्स अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे

गूगल लाया नया फीचर, पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए मेल

नई दिल्ली, एजेंसी

गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब आप अपनी ईमेल आईडी का यूजरनेम (@gmail.com से पहले वाला हिस्सा) बदल सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यह आपकी डिजिटल पहचान को अपग्रेड करने का एक तरीका है। फिलहाल यह अपडेट अमेरिकी यूजर्स के लिए है, जो उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अपना 'अजीब' यूजरनेम बदलना चाहते थे। आगे हम आपको इसे बदलने का पूरा प्रोसेस और पुराने एड्रेस से जुड़ी जरूरी बातें बताएंगे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने X पर पोस्ट कर लिखा, 2004 एक अच्छा साल था, लेकिन आपके Gmail एड्रेस को उसमें फंसे रहने की जरूरत नहीं है। अब यूजर्स को अपने पुराने या 'शर्मिंदा' करने वाले ईमेल एड्रेस

(जैसे- coolboy123) के साथ रहने की जरूरत नहीं है। गूगल अब इसे बदलने की सुविधा दे रहा है।' आपका पुराना एड्रेस एक 'अल्टरनेट ईमेल' बन जाएगा। पुराने और नए, दोनों एड्रेस पर आने वाले ईमेल आपको एक ही इनबॉक्स में मिलेंगे। आपके पुराने मेल, फोटोज, ड्राइव की फाइल्स और मैसेजेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप गूगल की सभी सर्विस (जैसे- मैप्स, यूट्यूब, ड्राइव) पर पुराने या नए, किसी भी ईमेल से लॉग-इन कर सकेंगे।

राहत : 100 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत

पोस्ट ऑफिस आरडी पर 6.7% ब्याज

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर (Q1FY27) के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट (RD) कराने का प्लान बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस RD आपके लिए सही रह सकती है। इस पर 6.70% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें 5 साल तक हर महीने 2 हजार रुपए जमा करने पर 1 लाख 43 हजार रुपए का एकमुश्त फंड तैयार कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट या RD बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकती है। आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहें और 5 साल बाद मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होगी। घर के गुल्लक में पैसे जमा करने पर भले ही आपको ब्याज नहीं मिले, पर यहां पैसे जमा करने पर आपको ब्याज भी मोटी

मिलती है। पोस्ट ऑफिस RD में अगर आप 1 हजार रुपए प्रति महीने की रकम इन्वेस्ट करते हैं, तो 6.7% सालाना ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद मैच्योर होने पर यह लगभग 71 हजार रुपए हो जाएंगे। RD पर लोन सुविधा भी मिलती है। यानी बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर आप बिना RD तुड़वाए इस पर लोन भी ले सकते है। इसमें पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज पर लोन मिलता है। पोस्ट ऑफिस की पांच साल वाली RD में अगर आप लगातार 12 किस्त जमा कर लेते हैं तो आप लोन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यानी ये सुविधा लेने के लिए आपको कम से कम एक साल लगातार रकम डिपॉजिट करनी होगी। एक साल बाद आप अपने अकाउंट में जमा राशि का 50% तक लोन ले सकते हैं। अगर आप RD पर लोन लेते हैं तो आपको लोन की रकम पर ब्याज 2% + RD खाते पर लागू ब्याज दर के रूप में लागू होगा। जैसे अभी RD पर 6.7% ब्याज मिल रहा है, ऐसे में अगर आप अभी RD पर ब्याज लेते है तो आपको 8.7% सालाना की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति RD अकाउंट खोल सकता है। छोटे बच्चों के नाम पर भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। 10 साल या उससे अधिक उम्र होने पर आप इसे खुद ऑपरेट कर सकते हैं। 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए इसमें अकाउंट खोल सकते हैं।

रणवीर सिंह कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म

धुरंधर फ्रैंचाइजी की सफलता के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि डायरेक्टर आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आदित्य धर रणवीर सिंह के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं।

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, आदित्य धर इस समय तीन स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं। इनमें द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा, एक ऐतिहासिक फिल्म और एक बड़े लेवल की स्पोर्ट्स फिल्म शामिल है। उनकी अगली फिल्म इनमें से कोई एक हो सकती है, जब तक कि कोई नया प्रोजेक्ट प्राथमिकता में न आ जाए।

एक सूत्र का कहना है कि द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस फिल्म पर उन्होंने पहले काफी काम किया था, लेकिन ज्यादा बजट के कारण इसे रोक दिया गया था। अब उनकी सक्सेस और इंडस्ट्री में बढ़ते भरोसे के चलते इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की संभावना बनी हुई है। एक अन्य सूत्र के मुताबिक, आदित्य धर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पर आधारित ऐतिहासिक फिल्म बनाने में भी दिलचस्पी रखते हैं।

पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने सैलरी नहीं

2 दिन पहले पेट्रोल पर 137 रुपए बढ़े, विरोध के बाद 80 रुपए कम किए

इसलामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान में इजराइल-अमेरिका की ईरान से जंग का असर दिख रहा है। वहां अगले 6 महीने तक मंत्रियों का वेतन रोक दिया गया है। दो दिन पहले पेट्रोल 137 रुपए और डीजल 184 रुपए महंगा किया गया था। हालांकि, देशभर में विरोध हुआ तो शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल 80 रुपए सस्ता कर दिया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डीजल बढ़ी हुई कीमत 520.35 रुपए प्रति लीटर पर ही मिलेगा। बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने कड़े उपायों का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट मंत्रियों की 2 महीने की सैलरी रोकने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब मंत्रियों को अगले 6 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा। शुक्रवार आधी रात को राष्ट्र को संबोधित करते हुए PM शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकार ने जनता पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल टैक्स को 80 रुपए घटाने का फैसला किया है। नई कीमतें देशभर के पेट्रोल पंपों पर तुरंत लागू हो गई हैं। शरीफ

पहले 458 के पार पहुंच गई थी कीमत

शहबाज सरकार ने दो दिन पहले पेट्रोल पर टैक्स 105 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया था। इससे यहां पेट्रोल की कीमत 321.17 रुपए से बढ़कर 458.41 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई थी। हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत भी 184.49 रुपए बढ़कर 520.35 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। हालांकि, डीजल पर लेवी को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतों में भी राहत देने की मांग उठ रही थी।

ने यह भी साफ किया कि पेट्रोल की ये कीमतें कम से कम अगले एक महीने तक स्थिर रहेंगी। सिर्फ पेट्रोल की कीमत घटाने तक ही राहत सीमित नहीं है, पीएम ने कई वर्गों के लिए डायरेक्ट सब्सिडी की घोषणा की है मोटरसाइकिल यूजर्स: इन्हें पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

इससे पहले भारत में भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई।

खाड़ी देशों के हालात को बताया महंगाई की वजह

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बंद होने की वजह से दुनियाभर में पेट्रोलियम सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन हफ्तों से तेल की कीमतें रोजाना बढ़ रही थीं, लेकिन हमने आम आदमी की मुश्किलों को देखते हुए इसका बोझ जनता पर नहीं डाला। सरकार ने इस दौरान करीब 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी।

पंचायत चुनाव में देरी पर सपा छात्र सभा का प्रदर्शन

'चुनाव टालना बंद करो' के नारे लगाए, लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया

- छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों और पुलिसवालों की भीड़ लग गई।
- पुलिस ने हिरासत में लेते हुए सभी छात्रों को गाड़ी में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया।
- 8 छात्रों ने हाथों में नारे लिखे पोस्टर लेकर हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी की।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सपा छात्र सभा से जुड़े 8 छात्रों ने लखनऊ में शनिवार को प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पंचायत चुनाव की तारीख घोषित की जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं ने "पंचायत चुनाव टालना बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो" जैसे नारे लगाए। हालात को काबू में रखने के लिए पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शनकारी जैसे ही हजरतगंज

8 छात्रों ने हाथों में नारे लिखे पोस्टर लेकर हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी की।

चौराहे से नारे लगाते हुए आगे बढ़े, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। गांववालों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल चुनाव की तारीख घोषित कर देना चाहिए। सरकार मनमानी तरीके से रवैया अपना रही है। अगर यह चाहती तो समय पर सब कुछ होता। भाजपा आम जनता को गुमराह करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि कोई भी चुनाव समय पर ना हो।

'आम जनता की भावनाओं से जुड़ा है पंचायत चुनाव'

सुल्तानपुर से प्रदर्शन में आए मनोज कुमार 'क्रांतिकारी' ने कहा कि यह सरकार संविधान को नहीं मानती। आम जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करती। यह सरकार सिर्फ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव समय पर करती है मगर आम जनता से जुड़ा हुआ ग्रामीण और किसानों से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा चुनाव पंचायती चुनाव होता है। पंचायती चुनाव सीधे आम जनता की भावनाओं और मुद्दों से जुड़ा होता। प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। पंचायती चुनाव टलने से सरकार की योजनाओं का लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह जाते हैं। चुनाव में जितना देरी होगी किसान उतना ज्यादा प्रभावित होगा।

छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों और पुलिसवालों की भीड़ लग गई।

'ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नाराजगी'

प्रदर्शन कर रहे प्रकाश मौर्या ने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत घबराहट है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। समय रहते चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई तो गांववालों का आक्रोश बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

गांववालों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल चुनाव की तारीख घोषित कर देना चाहिए। सरकार मनमानी तरीके से रवैया अपना रही है। अगर यह चाहती तो समय पर सब कुछ होता। भाजपा आम जनता को गुमराह करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि कोई भी चुनाव समय पर ना हो।

यूपी में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ताजा समीक्षा रिपोर्ट ने विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक की अवधि में प्रदेशभर में 1671 चालक ऐसे पाए गए, जिन्होंने एक भी किलोमीटर बस नहीं चलाई, फिर भी वेतन लेते रहे। इसके साथ ही 1069 परिचालक भी 'शून्य किमी' श्रेणी में दर्ज किए गए हैं।

यह आंकड़ा महज लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक ओर बसों के संचालन में स्टाफ की कमी बताई जाती रही, वहीं दूसरी ओर हजारों कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे हैं।

समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि कई क्षेत्रों में चालक और परिचालकों की कमी के चलते बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई रूट्स पर बसें समय पर नहीं चल पा रहीं या सेवाएं कम करनी पड़ रही हैं। इसके उलट बड़ी संख्या में चालक-परिचालकों को कार्यालय, स्टाफ कार संचालन और अन्य गैर-परिवहन कार्यों में लगा दिया गया, जिससे संचालन व्यवस्था असंतुलित हो गई। इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ रहा है।

खाने-पीने के सामान के दाम 20% तक बढ़े

7 मार्च से कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत, होटल-रेस्टोरेंट का काम प्रभावित

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की लगातार किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित हो रहा है। बीते कई हफ्तों से गैस आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के चलते कारोबारियों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनानी शुरू कर दी हैं। इससे खाने-पीने की चीजों के दाम 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने पूरे प्रदेश में गैस और ईंधन की आपूर्ति सामान्य होने का दावा किया है। लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में 7 मार्च से कॉमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत सामने आने लगी थी। गैस एजेंसियों की ओर से समय-समय पर पर्याप्त स्टॉक होने के दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति सुधरती नजर नहीं आई। कारोबारियों का कहना है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।

- गैस की किल्लत को देखते हुए दुकानदार ने लखनऊ में स्थायी चाय की भट्ठी बनवाई है।

जिला प्रशासन ने व्यवस्था लागू की कि गैस बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को सीधे घर पर डिलीवरी दी जाएगी। एजेंसियों पर लाइन नहीं लगेगी। इस फैसले के बाद वितरण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया, जिससे आपूर्ति और धीमी हो गई। इसका असर खासतौर पर कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर पड़ा है।

फास्ट न्यूज

शराब पीने से कारोबारी समेत तीन की मौत

मेरठ। मेरठ में शुक्रवार देर शाम शराब पीने के बाद किराना कारोबारी समेत तीन की मौत हो गई। तीनों ने एक सरकारी ठेके से देशी शराब खरीदी थी। वहीं पर तीनों साथ में पी रहे थे। तभी उन्हें उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। आनन फानन में तीनों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान बारी-बारी से तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना दौराला थाना क्षेत्र की है।

ट्रांसपोर्ट संचालक की संदिग्ध हालात में मौत

आगरा। आगरा में भोगीपुरा स्थित प्रकाश नगर में ट्रांसपोर्ट संचालक की संदिग्ध हालात में सड़क पर डेड बॉडी मिली है। इससे क्षेत्र में हड़कप मच गया। बॉडी को देख लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना शाहगंज को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉटम भेज दिया। शव की पहचान मेवाती गली निवासी अजगर अली (55) के रूप में हुई है। मृतक अजहर का कुछ महीनो से GST अधिकारी से विवाद चल रहा था। अजहर ने GST अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ अधिकार ने जुर्माना न देने के आरोप लगाए थे। इसके बाद अजहर ने अधिकारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। परिवार ने अजहर की मौत पर हत्या का आरोप लगा है। परिवार में अजहर की मौत से कोहराम मचा हुआ है। पत्नी सदमें है, घर में अन्य लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है।

राजमिस्त्री की गला घोटकर हत्या

कानपुर। कानपुर में चकेरी के पीएसी मोड़ पर किराए का कमरा लेकर अकेले रह रहे राजमिस्त्री की गला घोटकर हत्या कर दी गई। पत्नी और बच्चे फोन मिलाते रहे, लेकिन कॉल नहीं उठी। 18 घंटे से संपर्क न होने पर पत्नी ने एक परिचित युवक को फोन कर पति से बात कराने की बात कही, जब वह घर पहुंचा राजमिस्त्री का शव बेड पर औंधे मुंह पड़ा था। जहां रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ।

चारबाग समेत 52 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी

अब आउटर पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें, देशभर में टोटल 146 प्लेटफॉर्म का होगा विस्तार

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन समेत देश के 52 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की बड़ी तैयारी की गई है। इस योजना के तहत कुल 146 प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया जाएगा, जिससे 22 से 24 कोच वाली लंबी ट्रेनों को अब आउटर पर रुकने की मजबूरी से राहत मिलेगी। अभी प्लेटफॉर्म छोटे होने की वजह से कई बार ट्रेन की कुछ बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर रह जाती हैं, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में दिक्कत होती है। प्लेटफॉर्म छोटे होने का असर पार्सल सेवाओं पर भी पड़ता है। कई बार पार्सल वैन प्लेटफॉर्म से बाहर रह जाती है और बिना अनलोडिंग के ही ट्रेन को रवाना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म बढ़ने से यह समस्या भी खत्म हो जाएगी और लॉजिस्टिक्स सिस्टम बेहतर होगा। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 198 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। योजना के पहले चरण में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों को शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, अप्रैल के अंत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

सड़कों पर गंदगी देख भड़के प्रभारी मंत्री

मेयर के साथ 4 वार्डों में देखी सफाई व्यवस्था, एलएसए हेड को लगाई फटकार

- मेयर को इंदिरानगर में कई जगह सड़क किनारे कूड़े के ढेर मिले।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में सफाई व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। शनिवार को प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खर्कवाल ने शहर के 4 वार्डों में सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान उन्हें गंदगी तो दिखी ही, लोगों ने भी कूड़ा उठान न होने की शिकायत की। इस पर कार्यदायी कंपनी लखनऊ स्वच्छता अभियान (LSA) के हेड अभय रंजन को बुलाकर मेयर ने मौके पर ही फटकार लगा दी। मंत्री के निरीक्षण के दौरान मेयर के अलावा नगर आयुक्त गौरव कुमार भी मौजूद रहे। सभी लोग जोन-7 पहुंचे। यहां मैथिली शरण गुप्त वार्ड, इस्माइलगंज प्रथम, इंदिरानगर, बाबू जगजीवन राम वार्ड में जगह-जगह गंदगी मिली। सड़कों पर कूड़ा, नालियां चोक, ट्रांसफॉर्मर के आसपास गंदगी थी। यह देखते ही प्रभारी मंत्री भड़क गए। उन्होंने मेयर से कहा- जिम्मेदारों को चिह्नित कर एक्शन लें। इंदिरानगर से सफाई न होने की शिकायतें लगातार आ रही थीं। वहां पहुंचने पर मेयर ने सबसे पहले LSA हेड को मौके पर बुलाया। उनसे पूछा कि आपका एक आदमी तक नजर नहीं आ रहा है। सारी मेन रोड गंदी पड़ी हैं। LSA हेड अभय रंजन ने सफाई दी कि इस पर एक्शन लेंगे लेकिन मेयर ने उन्हें जमकर फटकार लगाई।

मंत्री बोले- गंदगी शहर की छवि खराब करती है

मंत्री ने साफतौर पर कहा कि नालियों की सफाई न होने से जलभराव और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। मच्छर पनपते हैं, डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। नगर आयुक्त से कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें चिह्नित कीजिए। मुख्य मार्गों और सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी मिलने पर मंत्री नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि गंदी सड़कें न सिर्फ शहर की छवि खराब करती हैं बल्कि ट्रैफिक और आमजन की आवाजाही को भी प्रभावित करती हैं। सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल स्थिति पर भी मंत्री ने कहा कि रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, सफाई नियमित होनी चाहिए। अतिक्रमण पर के सवाल पर मंत्री ने माना कि स्थायी अतिक्रमण अब भी बड़ी चुनौती हैं।

लोगों ने मेयर के सामने कहा कि यहां कूड़ा वाली गाड़ी नहीं आती है। इस पर मेयर ने जोनल अधिकारी रामेश्वर प्रसाद से कहा कि आज ही इनके घर के आसपास के 10 घरों में जाकर पता करिए कि कूड़ा गाड़ी आती है या नहीं? अगर नहीं आती तो कार्रवाई की जाएगी। आज शाम तक अधिकारी इसकी रिपोर्ट मुझे दें।

ओटी टेक्नीशियन ने निकाली थी एमबीए स्टूडेंट की किडनी

मेरठ के 3 डॉक्टरों के भी नाम सामने आए

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में MBA स्टूडेंट आयुष की किडनी किसी डॉक्टर ने नहीं, बल्कि एक ओटी टेक्नीशियन ने निकाली थी। उसी ने पारुल तोमर को किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था। डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने यह जानकारी को दी। उन्होंने बताया- आरोपी ओटी टेक्नीशियन मुदस्सर अली सिद्दीकी दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह फरार मिला। जिस मेडिलाइफ हॉस्पिटल में वह काम करता था, उसके तीनों मालिक भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक, इस कांड में मेरठ के तीन डॉक्टरों के नाम भी सामने आए हैं। ये सभी किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े डोनर और मरीजों का इंतजाम करते थे। अब तक कानपुर के इस चर्चित किडनी कांड में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तस्वीर एमबीए स्टूडेंट आयुष की है। शुक्रवार को पकड़े गए ओटी टेक्नीशियन ने दावा किया है कि आयुष की किडनी दिल्ली से साथ आए मुदस्सर अली सिद्दीकी ने निकाली थी। किडनी स्कैंडल केस की जांच डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी लीड कर रहे हैं। डीसीपी ने को बताया- ऑपरेशन में शामिल दो ओटी टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार को शुक्रवार को जेल भेजा गया। दोनों ने पुलिस पूछताछ में दिल्ली के रहने वाले मुदस्सर अली सिद्दीकी का नाम सामने रखा। उन्होंने बताया कि अली ने आयुष की किडनी निकाली और फिर पारुल तोमर का ट्रांसप्लांट किया।

शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा, दलाल

पॉलीटेक्निक संस्थानों में 'वर्किंग प्रोफेशनल्स' के लिए प्रवेश शुरू

लखनऊ। प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु कामगारों (WORKING PROFESSIONALS) के लिये सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म परिषद की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क रू0 300/- प्रति अभ्यर्थी जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रू0 200/- प्रति अभ्यर्थी निर्धारित है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.04.2026 निर्धारित है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश हेतु ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। प्रवेश हेतु अन्य कोई माध्यम मान्य नही होगा। विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in अथवा दूरभाष संख्या- 0522-2630106, 2630695, 2636667, 2636589 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बैठक : 3.62 लाख शिकायतों का निस्तारण, 7000 घंटे लाइव मॉनिटरिंग

डीसीसीसी के 4 साल पूरे, नगरीय सफाई मॉनिटरिंग में अहम भूमिका : ए.के. शर्मा

- स्वच्छता रैंकिंग सुधार में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की अहम भूमिका।
- 1533 हेल्पलाइन और 'संभव' पोर्टल से जनसमस्याओं का त्वरित समाधान।

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा द्वारा नगरी निकायों में नगरीय सुविधाओं एवं साफ-सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु स्थापित डेडीकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (DCCC) के सफल संचालन के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि मंत्री श्री शर्मा के सुझाव पर 4 अप्रैल 2022 को इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई थी। स्थापना के बाद से यह केंद्र लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरी निकायों की रैंकिंग सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने निदेशक श्री अनुज झा एवं अपर निदेशक श्रीमती ऋतु सुहास सहित पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2022 को मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद 4 अप्रैल 2022 को इस केंद्र की स्थापना की गई, जो तब से निरंतर क्रियाशील है और इंटीग्रेटेड भावना से कार्य कर रहा है।मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रारंभ में इस केंद्र में हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर 1533 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। साथ ही 'संभव' ऑनलाइन पोर्टल भी संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन आमने-सामने होकर समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने 'संभव' पोर्टल को एक अभिनव पहल बताया। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। जिन नगरी निकायों की स्वच्छता रैंकिंग नीचे है, उनका विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।उन्होंने आगामी वर्षाकाल के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्लांटेशन एवं अन्य स्वच्छता अभियानों को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर जोर दिया।उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कार्य की शुरुआत अपने आसपास से होती है, इसलिए रेहड़ी-पटरी पर कार्य करने वाले लोगों, गरीबों, सफाई कर्मियों एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पृष्ठ 01 का शेष...

शिक्षामित्रों को...

5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। साथ ही यह आदेश दिया है कि अनुदेशकों की नौकरी खत्म न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमैटिक तरीके से सृजित है। अनुदेशकों को 17 हजार रुपए मानदेय 2017 से लागू किया जाए। सीएम ने वाराणसी के सुबह 10 बजे शिवपुर के परिषदीय स्कूल में 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारंभ किया। बच्चों को खुद स्कूल बैग पहनाया। गिफ्ट और किताबें दीं। हालचाल पूछा। बाद में बच्चों को खुद खाना परोसा। सीएम ने कहा- पहले तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। किसी भी सड़क से जाओ तो बच्चे दिनभर घूमते मिलते थे। कोई तालाब में, कोई कीचड़ में, तो कोई भैंसों के साथ खेलता मिलता था। हम बच्चों से पूछते थे कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे। पता चलता था कि स्कूल दूर हैं। योगी ने कहा- स्कूली शिक्षा पर हम यूपी में 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करते हैं। इसका रिजल्ट आना चाहिए। जहां कस्तूरबा गांधी स्कूल नहीं थे, वहां इस बजट में हमने पैसा दिया। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 8वीं तक की पढ़ाई थी, जिसके बाद बच्चियां स्कूल जाना बंद कर देती थीं। हमने कहा कि इसे 12वीं तक करेंगे। मुझे याद है, जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी। हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे अलग-अलग जिलों में जाने का अवसर मिला था। मैंने बेसिक शिक्षा विभाग के भवनों की जर्जर स्थिति देखी। बंदी की कगार पर पहुंच रहे स्कूलों के बारे में जानकारी ली। मैं एक स्कूल में गया था, जहां प्रिंसिपल ने बताया कि उनके स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। 10 से कम बच्चे रह गए हैं। नए सत्र में शायद ये बच्चे भी न आएं। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं। जवाब मिला-बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है। तब मैंने प्रिंसिपल से कहा था- बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप में पढ़ाने की रुचि नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाना ही हमारा काम है। योगी ने कहा- याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है तो सबको शिक्षित करना होगा। पहले स्थितियां कैसी थीं? स्कूलों में बच्चों का ड्रॉपआउट रेट 19% से ज्यादा हो गया था। लेकिन अब ड्रॉपआउट रेट 19% से घटकर 3% पर पहुंच गया है। हमें इसे 0% पर लाना है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री लेना नहीं होता। शिक्षा इंसान को अच्छे संस्कार देने और सही रास्ता दिखाने का जरिया है।

केरलम में 339...

चुनाव लड़ रहे सभी दलों ने कम से कम 42% टिकट ऐसे कैंडिडेट्स को दिए हैं जिनपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 201 कैंडिडेट्स पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अलप्पुझा जिले की कुट्टनाड सीट से केरल कांग्रेस के रेजी चेरियन 2026 केरलम विधानसभा चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनकी कुल संपत्ति 218 करोड़ रुपए है। वहीं, कोट्टायम जिले की एट्टुमानूर सीट से SUCI(C) के आश्ना थम्बी की संपत्ति सिर्फ 84 रुपए है। 8 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति जीरो बताई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जहां 27% उम्मीदवार करोड़पति थे, वहीं 2026 में ये संख्या 39% हो गई। हर उम्मीदवार की औसत संपत्ति 2.78 करोड़ है। BJP के एक उम्मीदवार की एवरेज संपत्ति 5.7 करोड़, कांग्रेस की 3.93 करोड़ और CPI(M) की 2.3 करोड़ रुपए है। 2011 जनगणना के मुताबिक, केरलम देश के उन राज्यों में से है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। इसके बावजूद पार्टियों ने सिर्फ 11% (92) टिकट महिलाओं को दिए हैं। शिक्षा के मामले में भी केरलम देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है। चुनाव लड़ रहे 54% उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं हैं। वहीं, 48% उम्मीदवारों की शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच है। चुनाव लड़ रहे 16% (140) उम्मीदवार 25 से 40 साल के हैं। 41 से 60 साल के 58% (497) उम्मीदवारों हैं। इसके अलावा, 26% (224) उम्मीदवार 61 से 80 साल के हैं। 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है।

कांग्रेस चाहती है ...

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टीएमसी पार्षद भीष्मदेव कर्मकार की मौजूदगी में घटना हुई। केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग के दिन 18-30 साल के युवा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक 2 किमी के अंदर फ्री राइड मिलेगी, जबकि पहली बार वोट देने वालों को हलवा पैकेट दिया जाएगा। तमिलनाडु के लालगुडी में चुनावी फ्लाइंग स्क्वॉड ने 50 लाख रुपए कैश जब्त किए, जिसका कोई वैध हिसाब नहीं दिया जा सका। यह रकम TVK उम्मीदवार कू पा कृष्णन के एक रिश्तेदार के घर से बरामद हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुनेलवेली में चुनाव प्रचार के दौरान रजनीकांत का गाना गाकर DMK का घोषणापत्र समझाया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को गाली देने के का काम कर रही है, जिसे वे देश नाराज हो जाएं और वहां मौजूद भारतीयों को परेशानी है।

पीडीए को जिताकर संविधान बचाने का संकल्प लें युवा: अखिलेश यादव

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने युवाओं से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के पक्ष में माहौल मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बूथ स्तर तक युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ युवा मिलकर "पीडीए सरकार" बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान, अधिकार और आरक्षण की रक्षा के लिए पीडीए की सरकार जरूरी है। उन्होंने युवाओं को नारा देते हुए कहा— "पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में भाजपा किसी भी तरह की गड़बड़ी और चालबाजी कर सकती है, लेकिन सतर्क पीडीए युवा इसे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले फर्जी वोटरों पर नजर रखी जाएगी और सबूत के साथ कार्रवाई कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने युवाओं से अपील की कि वे उकसावे में न आएं और शांत, संयमित तरीके से काम करें। उन्होंने कहा कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर समाज को पीड़ा और अन्याय से मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा को सबसे कठिन चुनाव का सामना करना पड़ेगा और इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676